भाषा । साहित्य । संस्कृति

प्रश्नचिह्न

भाषा की तोतली ज़बान में
मेरे पहले शब्द 'माँ' या 'पा'
कुछ भी हो सकते थे
पहला बोला गया
पूरा वाक्य
कोई भी सुंदर वाक्य हो सकता था।

~ शिवांगी गोयल

वर्ष : 03 । अंक : 29 । अगस्त 2026

9 789334 470284

आवरण : वंशीलाल परमार

संपादक : आलोक रंजन

भाषा । साहित्य । संस्कृति

प्रश्नचिह्न

अगस्त 2026 । उनतीसवाँ अंक

प्रबंध सम्पादकः
राहुल राज

प्रबंध सहयोगः
सौरव कुमार भारती

सम्पादक
आलोक रंजन

आवरणः वंशीलाल परमार
रेखांकनः श्वेता कुमारी

अक्षर संयोजन
खुशी

प्रश्नचिह्न में प्रकाशित रचनाओं का सर्वाधिकार रचनाकारों के अधीन सुरक्षित है। प्रश्नचिह्न में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार, तथ्य लेखकों के अपने हैं। प्रश्नचिह्न में प्रकाशित रचनाओं के लिए प्रश्नचिह्न पत्रिका समूह का सहमत होना आवश्यक नहीं है और न ही पत्रिका इसके लिए उत्तरदायी है।

वार्षिक मूल्य :

व्यक्तियों के लिए-	600.00 रुपये
संस्थाओं और पुस्तकालयों के लिए-	1500.00 रुपये
विदेशों में-	$25

एक प्रति का मूल्य :

व्यक्तियों के लिए-	50.00 रुपये
संस्थाओं के लिए-	100.00 रुपये
विदेशों में-	$10

विज्ञापन दरें :

बाहरी कवर-	20,000.00 रुपये
अन्दर कवर-	15,000.00 रुपये
अन्दर पूरा पृष्ठ-	10,000.00 रुपये
अन्दर का आधा पृष्ठ-	7,000.00 रुपये

संपादकीय कार्यालयः

8/54 - ए, प्रथम तल, डबल स्टोरी,
विजय नगर, दिल्ली - 110009
मोबाइल : 9155113056

ई-मेल: prashanchinha.patrika@gmail.com
infoprashanchinha.patrika@gmail.com

वेबसाईट: www.prashanchinha.in

फेसबुक: https://www.facebook.com/prasnacihnapatrika

इंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/prashanchinha.in

अनुक्रम

सम्पादकीय

कविताएँ

शिवांगी गोयल, निर्मल गुप्त

श्याम कुमार, मुख़्तार अहमद, मयंक त्रिवेदी

कहानियाँ

डॉ. अनुज प्रभात

अवेद्य आलोक

आलेख

डॉ. लोकेन्द्रसिंह कोट

विनय सिंह बैस

समीक्षा

डॉ. मीरा सोनी

प्रकाश पुरोहित

विविध

डॉ. मनोरमा गौतम

डॉ. नितीन उपाध्ये

लाठियों के साये में सपने

झारखंड में जुलाई-अगस्त 2026 के दौरान चला JPSC–JSSC भर्ती परीक्षाओं से जुड़ा छात्र आंदोलन केवल कुछ परीक्षाओं को रद्द कराने की मांग भर नहीं था। यह उस बेचैनी की अभिव्यक्ति था जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के भीतर व्यवस्था की पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को लेकर जमा होती रही है। रांची में 26 दिनों तक चले आंदोलन के बाद सरकार ने JSSC-CGL सहित कुछ परीक्षाओं को रद्द करने तथा भर्ती परीक्षाओं में 2014 से हुई कथित अनियमितताओं की जाँच कराने की घोषणा की। इस पूरे घटनाक्रम को केवल सरकार बनाम छात्र के रूप में देखना समस्या को छोटा कर देना होगा। असली प्रश्न है- क्या किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक युवा को अपने अधिकार के लिए इतने लंबे संघर्ष, अनशन और सड़क पर उतरने के बाद ही सुना जाना चाहिए?

छात्रों की प्रमुख शिकायत भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को लेकर थी। आंदोलनकारियों ने JPSC और JSSC की विभिन्न परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की उच्चस्तरीय जाँच और केंद्रीय एजेंसी से जाँच की मांग उठाई। शुरुआती दौर में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद गतिरोध बना रहा। यहाँ सरकार की पहली बड़ी कमी समय पर संवाद न स्थापित कर पाना दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने बाद में संवाद और समाधान की बात कही, लेकिन छात्रों का आंदोलन कई दिनों तक चलने के बाद औपचारिक बातचीत शुरू हुई। लोकतंत्र में संवाद संकट उत्पन्न होने के बाद की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि शासन की नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा होना चाहिए।

दूसरी बड़ी समस्या भर्ती व्यवस्था पर भरोसे का संकट है। जब किसी परीक्षा में हजारों युवाओं का भविष्य जुड़ा हो, तब परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, निजी एजेंसी, प्रश्नपत्र की सुरक्षा, उत्तरपुस्तिका और परिणाम- हर स्तर पर पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वर्तमान घटनाक्रम में जाँच एजेंसियों की कार्रवाई और परीक्षा एजेंसियों से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी ने भी इस मामले की गंभीरता बढ़ाई है।